की देख-रेख बोर्ड आफ गवर्नर द्वारा की जाती है जिसमें सरकारी प्रतिनिधि होते हैं । बोर्ड आफ गवर्नर एन. सी. बी. के कार्य कलापों की निरन्तर समीक्षा करता है और जब कभी आवश्यक होता है, उपचारी उपाय शुरू करता है ।

Quality of India tractors

1259. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that quality of Indian tractors is much below the standard of tractors manufactured" 6y other countries;

(b) whether Government have received any complaint from the importing countries of Indian tractors in this regard;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what steps are being taken toremove the defi ctors to compete with the ot

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) and (b) Government is not aware of any adverse comment in terms of quality of Indian tractors in the global market. In fact, exports of Indian tractors are going up.

(c and (d) Do not arise.

Industrially backward districts in Gujarat

1260. SHRI ANANTRAY DEV SHANKER DAVE : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what is the number of districts in Gujarat which are industrially backward;

(b) whether Government are considering any proposal to include some new districts in that list;

(c) if so, what are the details of the districts;

(d) if the answer to part (b) above be in the negative, what are the reasons therefor; and

(e) what is the number of new industries set up during the last two years for the development of backward districts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE, IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) The number of industrially backward districts identified by the Central Government for Gujarat is eleven.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Government have decided that industrialisation of less industrialised areas would be through creation of infrastructural facilities under the Growth Centre Scheme announced in 1988.

(e) During the last 2 years, sixteen industrial licences have been issued for the backward districts of Gujarat. In respect of delicensed industries! 318 Industrial Entrepreneurs Memoranda have been filed for the backward districts of Gujarat.

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

1261. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य के औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराए गए संसाधनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर क्या थी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्र सरकार ने योजना सहायता के अतिरिक्त छठी तथा सातवीं योजना में संसाधन उपलब्ध कराए थे । पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन राजसहायता, केन्द्रीय निवेश राजसहायता तथा जिला उद्योग केन्द्र आदि द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को सीधी केन्द्रीय सहायता दी गई है । पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(रु० लाख में)

	1989-90	1990-91	1991-92
1. परिवहन राजसहायता	106.23	110.00	140.00
2. केन्द्रीय निवेश राजसहायता	179.60	—	—
3. डी० आई० सी० योजना	229.60	235.00	232.00
4. एस० एस० आई० एककों की गणना	19.71	27.41	12.19
5. विकास केन्द्र योजना	—	100.00	200.00
6. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	—	100.00	50.00
7. साथरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर	—	—	50.00

(ङ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन राज्यवार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकलित नहीं करता है ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की समितियों को दिया गया कर्ज

1262. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ शीम अफजल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की किन-किन समितियों को कितना-कितना कर्ज दिया और ऐसी समितियों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सूचना दी है कि उसने खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों हेतु आबंटित निधियों में से अनु. जाति/अनु. जनजातियों के लाभार्थियों को राज्य में उनकी जनसंख्या के भाग को आधार पर निधियां अलग करने के लिए अपने सभी कार्यान्वयन अभिकरणों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान अपने विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को दिए गए कुल ऋण इस प्रकार हैं :—

(रु० करोड़ में)

वर्ष	खादी ऋण	ग्रामोद्योग ऋण	योग
1990-91	23.88	87.70	111.58
1991-92	11.71	76.14	87.85